

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2579
दिनांक 04 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी विकास

2579. श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री बलभद्र माझी:

श्री अनूप संजय धोत्रे:

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

श्री खगेन मुर्मु:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

श्री शिवमंगल सिंह तोमर:

श्री सुनील कुमार:

श्री नव चरण माझी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा महाराष्ट्र, ओडिशा में नवरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में वाल्मीकि नगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र में अकोला जिले सहित राज्य-वार और जिला-वार दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अकोला जिले और ओडिशा में नवरंगपुर जिले सहित राज्य-वार और जिला-वार पिछले पांच वर्षों के दौरान नस्ल सुधार, चारा विकास और पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र, जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र में अकोला जिले तथा ओडिशा में नवरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार/जिला-वार पशुधन और डेयरी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) नवरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र में अकोला जिले सहित राज्य-वार और जिला-वार डेयरी कार्यों को बढ़ावा देने, पशुधन विकास के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजित करने, डेयरी पशुधन और मूल्य संवर्धन तथा दूध और पशुधन उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास दूध और पशुधन उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा पशुधन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए और पहल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो महाराष्ट्र, जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और अकोला जिले सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने डेयरी बुनियादी ढांचे, पशुधन रोग नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान और वैज्ञानिक पशुधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

- (छ) क्या सरकार के पास पशुधन और डेयरी विकास बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां. तो महाराष्ट्र, विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है,
- (ज) दूध उत्पादकता, ग्रामीण रोजगार और पशुधन किसानों की आय में वृद्धि पर एनएलएम का आकलन और प्रभाव क्या रहा है, और
- (झ) क्या सरकार का महाराष्ट्र में, विशेषकर जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, पशुधन और डेयरी विकास बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क और ख) देश में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) लागू किया जा रहा है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) कार्यान्वित कर रहा है। यह कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP), इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF), सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक, सीमन स्टेशनों के सुदृढीकरण के माध्यम से देश भर में गोपशु और भैंसों से दूध के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार के सभी जिले शामिल हैं।

RGM योजना गोपशु और भैंस की नस्ल सुधार के लिए का कार्यान्वित की जा रही है। NLM योजना भेड़, बकरी, सूअर, ऊँट, गधे और घोड़ों की नस्ल के विकास और चारा उत्पादन पर केंद्रित है। रोगों की रोकथाम के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पिछले पाँच वर्षों में RGM, LHDCP और NLM के अंतर्गत हुई प्रगति इस प्रकार है:

राष्ट्रीय गोकुल मिशन:

(i) NAIP कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 10.51 करोड़ पशुओं को शामिल करते हुए 17.27 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं जिससे 5.98 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र नबरंगपुर, ओडिशा, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, वाल्मीकि नगर, बिहार और महाराष्ट्र के अकोला जिले सहित, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार में किए गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या **अनुबंध-1** में दी गई है। इस योजना के अंतर्गत देश में 47,687 बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया गया है और शामिल किया गया है। MAITRI की तैनाती का राज्य-वार और जिले-वार विवरण, जिसमें लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र नबरंगपुर, ओडिशा, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, वाल्मीकि नगर, बिहार और महाराष्ट्र का अकोला जिला शामिल है, **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ii) देश में देसी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में 3 और बिहार राज्य में 2 प्रयोगशालाओं सहित, 24 IVF प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है। इन प्रयोगशालाओं से 29,283 व्यवहार्य भ्रूण तैयार किए गए, इनमें से 17,424 भ्रूणों को हस्तांतरित किया गया और 2,748 बछड़े/बछड़ियों का जन्म हुआ।

(iii) किसानों के द्वार तक तकनीक पहुँचाने के लिए IVF तकनीक का प्रयोग करके 'त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम' शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पशुओं की सुनिश्चित गर्भावस्था पर किसानों को 5000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7959 भ्रूण स्थानांतरित प्रत्यारोपित किए गए हैं, 1666 गर्भधारण हुए हैं और 1223 बछड़े/बछिया पैदा हुए हैं, जिनमें से 1142 मादा (बछिया) हैं।

(iv) उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों, जिनमें देसी नस्ल के सांड भी शामिल हैं, का प्रयोग करके 1.41 करोड़ सेक्स-सॉर्टेड सीमन डोज़ तैयार किए गए हैं। भारत पशुधन पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, सेक्स-सॉर्टेड सीमन का प्रयोग करके 9.71 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और इससे 7.82 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

(v) 48 सीमन केंद्रों को संस्वीकृति दी गई है, जिनमें महाराष्ट्र में 4 (राहुरी, नागपुर, औरंगाबाद और पुणे) और बिहार में एक (पूर्णिया) सीमन केंद्र शामिल हैं।

(vi) देश में 28 हीफर पालन केंद्र संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें बिहार में मुंगेर और डुमरांव केंद्र और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 500 हीफर की क्षमता वाला एक केंद्र शामिल है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन:

i. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, असम और राजस्थान राज्यों में भेड़ और बकरी के लिए पांच क्षेत्रीय सीमन केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए 6 बकरी सीमन बैंक अनुमोदित किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गोपशु-भैंस के 6,405 कृत्रिम गर्भाधान (AI) केंद्रों को बकरी के लिए AI सेवाएँ देने के उद्देश्य से अपग्रेड किया गया है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, असम और तमिलनाडु राज्यों में सूअर के सीमन का संग्रहण और प्रसंस्करण करने वाली नौ प्रयोगशालाओं को अनुमोदन दिया गया है।

ii. पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर, ऊँट, घोड़े और गधे के लिए 4084 नस्ल वृद्धि फार्मों को अनुमोदन दिया गया है।

iii. अब तक 1.61 लाख मीट्रिक टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीज का उत्पादन किया गया है।

iv. NLM-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के अंतर्गत 204 साइलेज और TMR बनाने वाली इकाईयों को अनुमोदन दिया गया है, जिनकी वार्षिक क्षमता 7.20 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।

v. वार्षिक 7000 मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता वाली तीन चारा बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाईयों को अनुमोदन दिया गया है।

पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम:

घटक का नाम	कुल
खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) नियंत्रण कार्यक्रम (टीकाकरण खुराक लाख में)	10801.76
ब्रूसेल्लोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (पात्र बछड़ियों का टीकाकरण खुराक लाख में)	296.74
पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (PPR) नियंत्रण कार्यक्रम (टीकाकरण खुराक लाख में)	1561.82
क्लासिकल स्वाइन फीवर नियंत्रण कार्यक्रम (CSF-CP) (उत्तर-पूर्वी राज्यों में सूअरों का टीकाकरण खुराक लाख में)	38.16
पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD) (टीकाकरण खुराक लाख में)	1850.57
मोबाइल पशुचिकित्सा इकाईयों का संचालन (MVU की संख्या)	4019

जलगांव जिले में: FMD टीकाकरण 38 लाख, ब्रूसेल्लोसिस टीकाकरण 0.69 लाख, CSF टीकाकरण 0.14 लाख और PPR: 10.82 लाख।

(ग) राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है। RGM, NLM, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और LHDCP के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध II** में है। NPDD, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) और NLM-EDP के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या **अनुबंध III** में है।

(घ) से (झ) पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) वर्ष 2014-15 से देश भर में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) योजना कार्यान्वित कर रहा है। NPDD योजना को निम्नलिखित दो घटकों के साथ लागू किया जा रहा है:

NPDD का घटक 'क' देश भर में गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण, दूध की शुरुआती खरीद और शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के सृजन और उसके सुदृढीकरण पर केंद्रित है। यह पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों (NER) और संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) में दूध प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना तैयार करने में भी सहायता करता है। इस घटक को देश भर में लागू किया जा रहा है।

NPDD योजना के घटक 'ख', "सहकारिता के माध्यम से डेयरी," का उद्देश्य किसानों की संगठित बाज़ार तक पहुँच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को अपग्रेड करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है। यह घटक नौ राज्यों में लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र और ओडिशा NPDD योजना के घटक 'ख' के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

NPDD योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता और संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का विवरण **अनुबंध-II और III** में दिया गया है।

इस के अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन, पशु आहार संयंत्र, तकनीक-आधारित नस्ल वृद्धि फार्म, पशु चिकित्सा दवाओं और वैक्सीन अवसंरचना, कृषि अपशिष्ट-से-संपत्ति (कृषि-अपशिष्ट) और प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण संबंधी अवसंरचना को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत, व्यक्तियों, FPO, MSME, निजी कंपनियों, डेयरी सहकारी समितियों और धारा 8 कंपनियों को आठ साल के लिए सावधि ऋण पर 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है। राज्य-वार संस्वीकृत डेयरी परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जलगांव सहित महाराष्ट्र राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योगकता योजना के माध्यम से पशुधन और डेयरी विकास अवसंरचना को सुदृढ करने का प्रस्ताव रखा है।

भारत सरकार ने डेयरी अवसंरचना के सुदृढीकरण, पशु रोगों के नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान और वैज्ञानिक तरीके से पशु प्रबंधन के लिए देश भर में, जिसमें महाराष्ट्र के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, निम्नलिखित योजनाओं को लागू करके कई पहलें की हैं:

- (i) डेयरी अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि।
- (ii) पशुधन रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
- (iii) कृत्रिम गर्भाधान और वैज्ञानिक पशुधन प्रबंधन के माध्यम से गोपशु और भैंस की नस्ल सुधार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन।

(iv) जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, ऊँट, घोड़े, गधे और सूअर की नस्ल सुधार और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन।

नीति आयोग ने EDP घटक सहित NLM योजना की विस्तृत समीक्षा की है। मूल्यांकन से पुष्टि होती है कि NLM से नस्ल विकास, पशु आहार और चारा सुरक्षा, क्षमता निर्माण और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रगति हुई है। अधिकतर लाभार्थियों ने पशुधन उत्पादकता में सुधार, आय में वृद्धि, इनपुट लागत में कमी और पशु चिकित्सा व विस्तार सेवाओं के साथ बेहतर जुड़ाव की बात कही है।

ओडिशा, बिहार और महाराष्ट्र में RGM के कार्यान्वयन का राज्य-वार विवरण

राज्य	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन			स्थापित मैत्री
	किए गए कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	कवर किए गए पशु	किसान लाभान्वित	
ओडिशा	7541385	5336851	3203775	1500
बिहार	6487060	4480677	2916361	5433
महाराष्ट्र	9922984	6870636	4070347	2020

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नबरंगपुर, ओडिशा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वाल्मीकि नगर, बिहार और महाराष्ट्र में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जलगांव और अकोला जिले में RGM के कार्यान्वयन का जिले-वार विवरण।

जिले	राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन			स्थापित मैत्री
	किए गए कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	कवर किए गए पशु	किसान लाभान्वित	
नबरंगपुर , ओडिशा	109845	142687	75830	7
बेतिया / पश्चिम चंपारण, बिहार	104650	150989	81045	94
जलगांव, महाराष्ट्र	250958	352865	147532	60
अकोला, महाराष्ट्र	84220	126746	59725	43

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2579

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी और अन्य

पिछले 3 वर्षों के दौरान में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत जारी निधि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
1	आंध्र प्रदेश	3538.38	3184.16	1500.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1965.31	0	830.99
3	असम	723.25	2163.34	1280.99
4	बिहार	0.00	0	3000.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0	609.69
6	गोवा	0.00	0	0.00
7	गुजरात	6542.58	2071.85	7669.24
8	हरियाणा	0.00	0	885.25
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	6119.52	1412.50
11	लद्दाख	0.00	42	10.53
12	झारखंड	0.00	1500	1385.35
13	कर्नाटक	2651.31	0	0.00
14	केरल	6546.27	3697.74	174.50
15	मध्य प्रदेश	4903	0	1000.00
16	महाराष्ट्र	3261.5	1444.56	600.31
17	मणिपुर	0.00	0	512.15
18	मेघालय	0.00	0	0.00
19	मिजोरम	847.37	0	74.21
20	नागालैंड	466.2	0	932.42
21	ओडिशा	0.00	1671.06	895.54
22	पंजाब	0.00	0	697.88
23	पुदुचेरी	0.00	213.41	50
24	राजस्थान	250	0	1970.07
25	सिक्किम	1097.87	0	1393.98
26	तमिलनाडु	10996.1	0	1525.72
27	तेलंगाना	3153.13	0	995.18
28	त्रिपुरा	0.00	0	975.00
29	उत्तर प्रदेश	9642.18	0	0.00
30	उत्तराखंड	6082	0	576.36
31	पश्चिम बंगाल	6500	0	1294.95

LHDCP के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में जारी निधि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	84.50	13.67
2	आंध्र प्रदेश	8534.26	7605.85	7595.98
3	अरुणाचल प्रदेश	621.28	654.25	613.07
4	असम	2299.69	4696.50	5432.95
5	बिहार	266.48	5481.63	6715.82
6	चंडीगढ़	2.77	7.82	2.37
7	छत्तीसगढ़	621.51	3488.98	2996.89
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	3.76	9.05	5.10
10	गोवा	80.15	85.51	21.14
11	गुजरात	1087.97	5243.59	4611.72
12	हरियाणा	1352.28	2734.67	2543.83
13	हिमाचल प्रदेश	64.75	785.75	1182.25
14	जम्मू और कश्मीर	1885.42	2036.97	1650.21
15	झारखंड	0.00	460.00	3021.99
16	कर्नाटक	7066.94	6157.62	6612.60
17	केरल (NADRS)	596.51	1224.04	1315.14
18	लद्दाख	60.27	245.16	272.14
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.75
20	मध्य प्रदेश	4889.02	7613.47	9444.01
21	महाराष्ट्र	7232.82	6464.19	4819.66
22	मणिपुर	271.32	464.39	949.41
23	मेघालय	129.49	707.03	421.73
24	मिजोरम	262.78	359.15	1865.77
25	नागालैंड	115.48	126.51	412.75
26	ओडिशा	318.10	1240.09	999.12
27	पुदुचेरी	11.48	48.52	55.52
28	पंजाब	0.00	397.93	1680.00
29	राजस्थान	635.11	5968.58	8363.26
30	सिक्किम	251.07	312.61	374.36
31	तमिलनाडु	644.51	2259.60	4046.90
32	तेलंगाना	0.00	400.00	2422.53
33	त्रिपुरा	59.76	573.37	653.96
34	उत्तर प्रदेश	19259.84	15076.02	15534.67
35	उत्तराखंड	1998.68	1957.16	2362.23
36	पश्चिम बंगाल	3639.00	4034.63	4202.21
	कुल	64262.50	89005.14	103215.71

पिछले तीन वर्षों के दौरान NLM के अंतर्गत जारी की गई निधि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी वर्ष 2023-24	जारी वर्ष 2024-25	जारी वर्ष 2025-26
1	आंध्र प्रदेश	1260.00	786.50	367.75
2	बिहार	0.00	0.00	100.00
3	छत्तीसगढ़	75.00	50.00	116.18
5	गुजरात	0.00	100.00	240.00
6	हरियाणा	407.50	975.00	571.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	106.25
9	झारखंड	64.00	0.00	25.00
10	कर्नाटक	781.70	725.00	399.50
11	केरल	0.00	50.00	50.00
12	मध्य प्रदेश	350.00	250.00	735.00
13	महाराष्ट्र	65.00	30.00	15.00
14	ओडिशा	446.25	250.00	250.00
16	राजस्थान	0.00	100.00	100.00
17	तमिलनाडु	0.00	150.00	225.00
18	तेलंगाना	0.00	50.00	75.00
19	उत्तर प्रदेश	100.00	771.00	225.00
20	उत्तराखंड	198.48	306.25	550.00
21	पश्चिम बंगाल	0.00	302.00	325.00
22	अरुणाचल प्रदेश	573.70	181.25	337.20
23	असम	0.00	400.00	374.17
24	मणिपुर	0.00	170.30	301.25
25	मेघालय	0.00	0.00	114.00
26	मिजोरम	201.99	0.00	657.24
27	नागालैंड	50.00	193.90	300.08
28	सिक्किम	93.21	0.00	903.40
29	त्रिपुरा	183.47	0.00	458.52
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
31	जम्मू और कश्मीर	100.00	250.00	910.44
32	पुदुचेरी	0.00	0.00	39.56
33	लद्दाख	0	27.5	229.5

पिछले तीन वर्षों के दौरान NPDD योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि का विवरण (वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26)

	राज्य का नाम	जारी की गई निधियां* (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	3335.23
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3	असम	2507.17
4	बिहार	2463.10
5	छत्तीसगढ़	384.00
6	गोवा	0.00 #
7	गुजरात	4868.05
8	हरियाणा	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	2247.56
10	जम्मू और कश्मीर	2570.37
11	झारखंड	636.33
12	कर्नाटक	7684.47
13	केरल	2201.20
14	लद्दाख	1208.05
15	मध्य प्रदेश	5214.90
16	महाराष्ट्र	692.15
17	मणिपुर	0.00 #
18	मेघालय	787.92
19	मिजोरम	6.98
20	नागालैंड	24.24
21	ओडिशा	706.10
22	पुदुचेरी	595.56
23	पंजाब	5305.53
24	राजस्थान	6988.46
25	सिक्किम	1844.44
26	तमिलनाडु	9525.07
27	तेलंगाना	727.94
28	त्रिपुरा	704.69
29	उत्तर प्रदेश	756.20
30	उत्तराखंड	2118.07
31	पश्चिम बंगाल	0.00

*इसमें वर्ष 2023-24 से पहले संस्वीकृत, चल रही परियोजनाओं में जारी की गई निधियां शामिल हैं।

#पिछली परियोजनाओं के अंतर्गत अव्ययित बकाया के कारण निधियां जारी नहीं की गई।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2579
दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत
श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी और अन्य

NPDD के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	4
4	बिहार	2
5	छत्तीसगढ़	2
6	गोवा	1
7	गुजरात	3
8	हरियाणा	1
9	हिमाचल प्रदेश	3
10	जम्मू और कश्मीर	2
11	झारखंड	2
12	कर्नाटक	9
13	केरल	5
14	लद्दाख	2
15	मध्य प्रदेश	5
16	महाराष्ट्र	2
17	मणिपुर	1
18	मेघालय	1
19	मिजोरम	1
20	नागालैंड	1
21	ओडिशा	1
22	पुदुचेरी	4
23	पंजाब	2
24	राजस्थान	10
25	सिक्किम	2
26	तमिलनाडु	4
27	तेलंगाना	2
28	त्रिपुरा	2
29	उत्तर प्रदेश	2
30	उत्तराखंड	1
31	पश्चिम बंगाल	0
	कुल	77

AHIDF के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता।

1. नस्ल सुधार तकनीक तथा नस्ल वृद्धि फार्म

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	3	12.42
असम	9	125.76
बिहार	1	30.10
छत्तीसगढ़	19	962.40
गुजरात	4	257.55
हरियाणा	3	38.64
जम्मू और कश्मीर	1	1.01
झारखंड	4	25.17
कर्नाटक	22	256.80
केरल	1	1.34
मध्य प्रदेश	5	27.72
महाराष्ट्र	29	472.85
ओडिशा	6	42.33
पंजाब	6	108.56
राजस्थान	5	26.25
तमिलनाडु	17	400.16
तेलंगाना	2	34.78
उत्तर प्रदेश	8	153.51
उत्तराखंड	1	0.80
पश्चिम बंगाल	16	251.31
कुल योग	162	3,229.42

2. डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	16	1,310.45
असम	2	113.80
बिहार	2	120.61
दिल्ली	2	125.16
गुजरात	18	3,078.74
हरियाणा	11	314.30
हिमाचल प्रदेश	1	2.96
झारखंड	4	115.07
कर्नाटक	5	192.48
केरल	1	1.92
मध्य प्रदेश	14	490.23
महाराष्ट्र	52	3,340.22

ओडिशा	4	35.91
पंजाब	3	166.51
राजस्थान	13	213.07
तमिलनाडु	13	1,777.02
तेलंगाना	9	896.08
उत्तर प्रदेश	23	1,403.40
उत्तराखंड	1	86.32
पश्चिम बंगाल	8	283.58
कुल योग	202	14,067.85

3. मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	4	469.21
असम	1	50.21
बिहार	1	42.77
दिल्ली	1	51.00
हरियाणा	8	372.68
हिमाचल प्रदेश	2	53.60
कर्नाटक	2	93.61
केरल	1	7.98
महाराष्ट्र	3	431.26
ओडिशा	1	38.84
पंजाब	7	300.66
तमिलनाडु	6	237.76
तेलंगाना	2	154.43
उत्तर प्रदेश	1	8.01
पश्चिम बंगाल	1	16.63
कुल योग	41	2,328.65

4. पशु चिकित्सा टीके और दवा उत्पादन सुविधाएं

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	1	3.87
गुजरात	1	55.05
हरियाणा	1	36.00
मध्य प्रदेश	2	180.69
महाराष्ट्र	1	22.00
कुल योग	6	297.61

.NLM-EDP के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजना की राज्य-वार संख्या

राज्य	कुल	परियोजना लागत करोड़ रुपये में
आंध्र प्रदेश	330	272.79
अरुणाचल प्रदेश	83	53.82
असम	50	32.68
बिहार	2	0.70
छत्तीसगढ़	29	17.43
गुजरात	13	12.49
हरियाणा	27	19.06
हिमाचल प्रदेश	21	11.46
जम्मू और कश्मीर	27	12.23
झारखंड	2	2.49
कर्नाटक	1158	815.82
केरल	26	14.59
मध्य प्रदेश	507	377.41
महाराष्ट्र*	438	265.38
मणिपुर	11	5.17
मिजोरम	94	57.44
नागालैंड	95	41.66
ओडिशा	4	3.67
पुदुचेरी	1	0.64
पंजाब	24	17.58
राजस्थान	189	107.39
सिक्किम	12	7.32
तमिलनाडु	214	142.44
तेलंगाना	513	446.21
त्रिपुरा	37	25.75
उत्तर प्रदेश	285	146.15
उत्तराखंड	84	38.77
पश्चिम बंगाल	15	8.25
कुल	4291	2,956.79

जलगांव और अकोला के लिए संस्वीकृत परियोजनाएं

राज्य	ज़िला	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
महाराष्ट्र	जलगांव	6	4.12
महाराष्ट्र	अकोला	4	1.91

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी परियोजना अनुमोदित नहीं की गई थी।